

## 20वीं सदी में शराब विरोधी आन्दोलन का ऐतिहासिक अध्ययन:- उत्तरांचल के विशेष संदर्भ में



**अर्जुन सिंह**

शोधार्थी

इतिहास विभाग,

हे0न0ब0ग0 विश्वविद्यालय,

गढ़वाल, उत्तराखण्ड, भारत

### सारांश

20वीं सदी में उत्तरांचल में विविध स्थानीय समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय स्तर पर आन्दोलन चले, जिनका नेतृत्व स्थानीय नेताओं, महिलाओं, जनसमुदाय ने किया। आन्दोलनों में कुली बेगार, डोला पालकी, वन आन्दोलन, गाड़ी-सड़क आन्दोलन, शराब बंदी, आदि लोकप्रिय रहे। इन्हीं में एक शराब विरोधी आन्दोलन 20वीं सदी के प्रारंभिक दौर से ही न केवल राष्ट्रीय स्तर पर वरन स्थानीय स्तर पर महिला सक्रियता वाले स्वयं स्फूर्त आन्दोलन के रूप में शुरू हुआ।

शराब के दुष्परिणामों से चिंतित होकर छिटपुट रूप से मदिरा सेवन का विरोध हमेशा से की किया जाता रहा है। फिर भी शराब सेवन की परम्परा औपनिवेशिक शासकों की देन है, पाश्चात्य सम्पर्क में आने से भारतीयों में भी शराब का प्रचलन होता गया। जो समाज में बड़ी समस्या के रूप में उभरी, अतः गाँधी जी के नेतृत्व में चले आन्दोलन में शराब प्रमुख मुद्दा बना रहा, गाँधीवादी आन्दोलन से उत्साहित होकर स्थानीय स्तर पर शराब बंदी के समर्थन में आन्दोलन प्रारम्भ हुये। ब्रिटिश गढ़वाल में भी शराब बंदी आन्दोलन शुरू हुआ। औपनिवेशिक नुमाइन्दों ने भी पहाड़ में शराब के प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। परिणामस्वरूप शराब की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण सामाजिक अशांति, असुरक्षा, लोगों की आर्थिकी पर भुरा, नैतिकता का पतन, आदि तमाम समस्यायें उत्पन्न होनीं लगी। अन्ततः इन समस्याओं के मूल शराब संस्कृति के विरुद्ध जबरदस्त आन्दोलन शुरू हुआ।

**मुख्य शब्द** : मदिरा, गाँधीवादी, नुमाइन्दो, संस्कृति, औपनिवेशिक, नैतिकता।

**प्रस्तावना**

20वीं सदी में उत्तरांचल में विविध सामाजिक समस्याओं को लेकर आन्दोलन हुये, जिनका नेतृत्व स्थानीय नेताओं, महिलाओं, जनसमुदायों ने किया। आन्दोलनों में कुली बेगार, डोला पालकी, वन आन्दोलन, गाड़ी-सड़क आन्दोलन, शराब बंदी एवं विश्वविद्यालय आन्दोलन आदि लोकप्रिय रहे हैं। इन्हीं में एक शराब विरोधी आन्दोलन 20वीं सदी के प्रारंभ से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु पर्वतीय प्रदेश उत्तरांचल में भी व्यापक स्तर पर हुआ। जिसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। आन्दोलन असंगठित रूप से वर्तमान में भी निरंतरता बनाये रखा है।

**अध्ययन का उद्देश्य**

शोध छात्र का शोध पत्र लिखने का प्राथमिक उद्देश्य पर्वतीय अंचलों में शराब संस्कृति का प्रचलन कैसे हुआ को उजागर करना है। द्वितीय उद्देश्य मद्यसेवन से होने वाले अशंतोष को रेखांकित करना है, तथा इस कुप्रथा के विरुद्ध होने वाले जन आन्दोलन को पाठकों के समक्ष लाना है। और सबसे महत्वपूर्ण आन्दोलन के असफलताओं एवं सफलताओं का मूल्यांकन करते हुये आन्दोलन की प्रसंगिकता को उजागर करना है।

नशे के रूप में शराब सेवन मानवीय उपयोग में लाये गये विभिन्न व्यसनों में से एक है। व्यसनों के नकारात्मक प्रभावों को न केवल व्यक्ति, परिवार, समाज बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। इस समस्या से चिंतित होकर छिटपुट रूप से मदिरा सेवन का प्रतिरोध हमेशा से किया जाता रहा है। जिसके बारे में जानकारी अर्थशास्त्र,<sup>1</sup> स्मृतिग्रंथों<sup>2</sup> मध्यकालीन राजनीति शास्त्रों<sup>3</sup> एवं शासकों के शासनादेशों<sup>4,5</sup> में मिलते हैं। फिर भी शराब सेवन की वर्तमान परम्परा ब्रिटिश शासन की देन है। पाश्चात्य सम्पर्क में आने से भारतीयों में भी धीरे-धीरे शराब का प्रचलन होता गया। यूरोपीय परम्परा भारतीयों की लत में परिवर्तित होने लगी। अंग्रेजों द्वारा चीन<sup>6</sup> में अपनाई गई अफीम नीति के समान भारत में भी अंग्रेजों ने शराब का खूब प्रचार-प्रसार किया ताकि अधिक से

अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सके। यद्यपि राजस्व के लिये शराब का प्रयोग प्रारम्भ से ही किया जाता रहा है, कौटलीय अर्थशास्त्र में शराब से प्राप्त राजस्व संग्रहण के लिये तो पृथक सुराध्यक्ष विभाग की स्थापना की बात की गई है,<sup>7</sup> फिर भी अंग्रेजी सरकार ने इस नीति का व्यापक स्तर पर पालन किया। राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान शराब सेवन समाज में एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी जिसका सर्वाधिक नकारात्मक असर महिलाओं एवं बच्चों को झेलना पड़ा। अतः गाँधी जी के नेतृत्व में हुये आन्दोलन में मद्यशालाओं पर धरना प्रदर्शन एवं शराब का बहिष्कार अभिन्न अंग के रूप में जुड़ा रहा, गाँधी जी के नेतृत्व शराब के बहिष्कार को व्यापक स्तर पर सफलता मिली। गाँधीवादी आन्दोलन से उत्साहित होकर स्थानीय स्तर पर भी शराब बंदी के समर्थन में आन्दोलन प्रारम्भ होने लगे।

औपनिवेशिक कालीन उत्तरांचल में भी शराब सेवन एक बड़ी सामाजिक समस्या के रूप में उभरी। जिसके विरुद्ध सशक्त आन्दोलन शुरू हुआ। यद्यपि पर्वतीय क्षेत्रों में पारम्परिक मद्य सेवन की परम्परा पूर्वकाल से चली आ रही थी,<sup>8</sup> किन्तु यह कभी भी समस्या का कारण नहीं बनी। जब तक कि प्रदेश पाश्चात्य संपर्क में नहीं आया। जैसे-जैसे पर्वतीय अंचल पाश्चात्य संपर्क में आता गया मद्यपान की नई संस्कृति से सामना हुआ। शहरों, छावनियों के निर्माण, स्थानीय लोगों के सेना में प्रवेश, विविध सरकारी कार्यालयों, पर्यटकों द्वारा, पर्वतीय क्षेत्रों में कच्ची शराब प्राप्ति की सुगमता एवं सबसे महत्वपूर्ण ब्रिटिश सरकार के अधिक से अधिक राजस्व संग्रहण नीति के कारण पहाड़ों में मद्य संस्कृति का प्रसार हुआ। बिकेट(1860) ने अपने बन्दोबस्त विवरण में स्वीकार किया कि कुमाऊँ के लोग शराब नहीं पीते।<sup>9</sup> 1861 में कुमाऊँ के सीनियर कमिश्नर गाइल्स ने आबकारी प्रशासन की रिपोर्ट में कहा है कि अभी भी पहाड़ी लोग नशे के व्यसन से मुक्त हैं।<sup>10</sup> कुमाऊँ कमिश्नर हेनरी रेम्जे(1856-84) ने वर्णन किया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में शराब का सेवन नहीं किया जाता, और न ही इसकी संभावना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि छावनियों और सैनिक चौकियों के अतिरिक्त शराब की दुकानें कहीं नहीं खुलने दी जायेगी।<sup>11</sup> संभवतः उक्त प्रशासकों ने पहाड़ों में अंग्रेजी शराब के प्रचलन का नहीं होने का विवरण दिया है। क्योंकि देशी शराब (कच्ची शराब) का उत्पादन एवं उपभोग पहाड़ों में पूर्वकाल से होता चला आ रहा था। अंग्रेजी शासन ने देशी शराब के उत्पादन पर कुछ पाबंदियाँ अवश्य लगाईं, किन्तु उसका कारण शराब को राजस्व व्यवस्था के अन्तर्गत लाना था। 1912-13 में गढ़वाल गजेटियर वाल्टन ने वर्णन किया है कि गढ़वाल में आबकारी विभाग द्वारा सर्वाधिक ऊँची बोली लगाने वाले को ही शराब निर्माण का विशेषाधिकार दिया जाता है और पिछले दस वर्षों में आबकारी से मिलने वाली सरकारी आय तीन गुनी हो गई है।<sup>12</sup> शीघ्र ही प्रशासन रेम्जे आदि के बातों से मुकर गई, औपनिवेशिक नुमाइन्दों ने पहाड़ में शराब के प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। शराब भू-राजस्व एवं वनों से मिलने वाले राजस्व के बाद आय का सबसे बड़े स्रोत में से एक था। नशे की प्रवृत्ति को

प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ग्रामीण अंचलों में कच्ची शराब के निर्माण को लाइसेंस प्रणाली के आधार पर नियमित किया गया<sup>13</sup> एवं शहरों में अंग्रेजी शराब की दुकानें स्थापित की गईं। फिर भी 1940-50 के दशक तक पर्वतीय क्षेत्रों में अंग्रेजी शराब का प्रचलन कम ही था। 1950 के बाद संचार मार्गों के विकास के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी विदेशी शराब का प्रयोग तेजी से होने लगा। खासकर 1960 के दशकों में जब सीमांत प्रदेशों के विकास पर ध्यान दिया जाने लगा, अतः मैदानी क्षेत्रों से संपर्क होने से अंग्रेजी शराब पहाड़ों में तेजी से बढ़ने लगी।<sup>14</sup> समय के साथ आबकारी राजस्व में भी वृद्धि होने लगी। 20वीं सदी के प्रारम्भिक दो दशकों में प्रशासन को शराब से मिलने वाली कुल राजस्व 131440/रूपये था<sup>15</sup>। 1930 के दशक में उग्र मद्यनिषेध आन्दोलन से यद्यपि शराब के बिक्री पर कुछ हद तक अंकुश लगा रहा, फिर भी पूर्ण शराब बंधी लागू नहीं की जा सकी। 1939-40 के सरकारी सत्र (बजट सत्र) में देहरादून से मिलने वाले कुल राजस्व 6794/रूपय एवं कुमाऊँ-गढ़वाल से 1717/रूपय राजस्व संग्रहण किया गया।<sup>16</sup> 1937 में कांग्रेसी शासन वाले संयुक्त प्रान्त के कुछ मैदानी क्षेत्रों जौनपुर, बदायूँ, एटा, बिजनौर आदि में शराब बंधी लागू की गई किन्तु पहाड़ों में मद्यविरोधी आन्दोलन के बाबजूद भी पूर्ण उपेक्षा की गई। फलस्वरूप 1946 में उत्तरांचल से आबकारी राजस्व बढ़कर 26,99,465/रूपय हो गया<sup>17</sup> पहाड़ों में शराब प्रचलन आगल प्रशासन के व्यवसाहिक नीति के साथ प्रारम्भ हुआ, जनसंघर्षों के बाद भी इससे प्राप्त होने वाले राजस्व में भी साल दर साल इजाफा होता रहा और पृथक राज्य बनने के बाद भी उत्तराखण्ड में 2001 में कुल राजस्व 203.60 करोड़ था यह 2004 में बढ़कर 300 करोड़ तक पहुँच गया।<sup>18</sup> शराब की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण लोगों की आर्थिकी पर बुरा असर पड़ रहा था, नशे ने आम जनता के स्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभाव, नैतिकता का पतन, बच्चों एवं पुरुष वर्ग में शराब की लत बढ़ने लगी, 1971 में उ०प्र० सरकार ने भी स्वीकार किया है।<sup>19</sup> इन तमाम समस्याओं के कारण अपराधों में वृद्धि के साथ सामान्य जनजीवन में अशान्ति और असुरक्षा उत्पन्न होने लगी। उक्त बातों से प्रबुद्ध वर्ग भी भली भाँति परिचित था।<sup>20</sup> अन्ततः इन समस्याओं की जड़ शराब के विरोध के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था। अतः 20वीं सदी के प्रारम्भ से ही शराब के बहिष्कार के लिये आन्दोलन शुरू हुआ। यद्यपि प्रारम्भ में मुख्यतः यह आन्दोलन कच्ची(देशी) शराब के विरुद्ध चला।<sup>21,22</sup> किन्तु शहरी केन्द्रों एवं बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में विदेशी शराब के खिलाफ भी आन्दोलन शुरू किया गया।

पर्वतीय प्रदेश में शराब विरोधी आन्दोलन स्वतन्त्र रूप से बिना किसी बाह्य समर्थन से 20वीं सदी के प्रारम्भ से शुरू हो चुका था फिर भी महात्मा गाँधी के नेतृत्व में चलाये गये मद्यनिषेध आन्दोलन के बाद ही प्रदेश में आन्दोलन ने गति पकड़ी। जिसकी बागडोर स्थानीय स्तर के नेताओं एवं महिलाओं के हाथों में थी। शराब की समस्या एवं निवारण को लेकर आन्दोलन अनवरत रूप से आजादी से पूर्व एवं पश्चात चलता रहा।

**आजादी से पूर्व शराब विरोधी आन्दोलन**

पर्वतीय अंचलों में पहली बार शराब के विरोध में आवाज अल्मोड़ा अखबार ने उठायी। अखबार के 2 जनवरी 1893 के अंक में सरकार के शराब के व्यवसायिक प्रवृत्ति की निन्दा की गई और कहा कि अफीम और शराब से लोग स्वास्थ्य और संपत्ति खोते जा रहे हैं, यहाँ तक कि वे चोरी, हत्या एवं अन्य अपराध करने में भी संकोच नहीं करते, फिर भी सरकार राजस्व प्राप्ति के लिये इन पदार्थों को प्रोत्साहन दे रही है। अखबार ने यह भी सिफारिश की कि नशीले पेय पदार्थों पर शीघ्र ही रोक लगाई जाये।<sup>23</sup>

पहली बार शराब के विरोध में प्रदर्शन 1907 में बागेश्वर एवं चौखुटिया में किया गया, जन प्रतिरोध के कारण उक्त स्थानों में शराब की दुकानें शीघ्र ही बन्द करनी पड़ी।<sup>24</sup>

1930-32 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान शराब के बहिष्कार को अभूतपूर्व सफलता मिली। महिलाओं ने जमकर शराब के दुकानों में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किये विभिन्न क्षेत्रों में शराब की दुकानें तोड़ी गई परिणामस्वरूप गाँधी इरविन समझौते में सरकार ने शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को विधि सम्मत मान लिया। गाँधीवादी आन्दोलन का व्यापक असर उत्तरांचल में भी हुआ। इसी दौरान पर्वतीय प्रदेश में मद्य निषेध आन्दोलन ने उग्र रूप धारण किया, शराब की दुकानों एवं शराब की भट्टियों पर धरना प्रदर्शन किये गये। 1930 में अल्मोड़ा में विश्नी देवी शाह, दुर्गा देवी, बची देवी एवं कुंती वर्मा के नेतृत्व में 100 से भी अधिक महिलाओं ने संगठित होकर शराब की दुकानों को तोड़ते हुये कारावास गयी।<sup>25</sup> दुर्गादेवीपंत, जीवंती ठकुरानी ने रानीखेत में और पद्मावती, भागीरथी देवी चौहान आदि ने हल्द्वानी में शराब की भट्टियों के आने धरने दिये।<sup>26</sup> 7 मई 1930 को सत्यग्रही जगमोहन सिंह नेगी, छवाण सिंह, नारायणदास महन्त के नेतृत्व में जनसमूह ने लैसडौन तहसील के अधिकांश शराब की दुकानों एवं भट्टियों को योजनाबद्ध ढंग से नष्ट कर दिया।<sup>27</sup> तल्ला उदयपुर क्षेत्र में डबलसिंह नेगी के नेतृत्व में 12 सत्यग्रहियों के दल ने शराब भट्टियों पर धरना देकर नष्ट करने का प्रयत्न किया।<sup>28</sup> अन्ततः सत्याग्रही उदयपुर क्षेत्र में शराब उत्पादन केन्द्रों को बन्द करने में सफल हुये। ब्रिटिश गढ़वाल के राजनैतिक गतिविधियों के केन्द्र कोटद्वार,दुग्डडा में प्रताप सिंह नेगी और बलदेव सिंह आर्य के नेतृत्व में शराब भट्टियों और दुकानों की नाकाबन्धी का अभियान चलाया गया, जिसमें अनेक स्वयं सेवकों ने भाग लिया, नाकाबन्धी के तहत नशेडियों को दुकानों तक नहीं पहुँचने दिया गया। अन्ततः जिलाधिकारी एक्टन ने पुलिस के सहायता से धरना दे रहे आन्दोलनकारियों पर लाठी बरसाई गई सत्याग्रहियों को बन्दी बनाकर कारावास में डाला गया। 1932 में जनपद देहरादून में शराब के भट्टियों पर धरना देने का कार्यक्रम बनाया गया कार्यक्रम में महिलाओं, साधु संतों एवं डी0ए0वी0 कालेज के छात्रों में जुलूस निकालकर शराब की दुकानों एवं होटलों में खडे अंग्रेज सैनिकों पर पथरा किया। प्रशासन ने इन आन्दोलनकारियों को गाडियों में भरकर शहर से दूर जंगलों में छोड़ने की नीति

अपनाई तथा कुछ को कारावास की सजा दी गई<sup>29,30,31</sup> सत्याग्रहियों के प्रति दमनात्मक नीति अपनाये जाने के पीछे स्पष्ट कारक राजस्व में हो रही कमी थी।<sup>32,33</sup> 1937 में जिन प्रान्तों में कांग्रेसी सरकार बनी, वहाँ मद्यनिषेध प्रमुख मुद्दा बना रहा, यद्यपि मद्रास, बाम्बे प्रान्तों में मद्यनिषेध लागू किया गया, किन्तु सयुक्त प्रान्त में कुछ ही मैदानी जिलों एटा, मैनपुरी, बदायूँ, बिजनौर,जौनपुर आदि में शराब बन्धी लागू की गई।<sup>34</sup> 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान महिलाए पुनः मद्यनिषेध गतिविधियों में सक्रिय हुईं। पर्वतीय प्रदेशों में भारी जनसंघर्ष के बाद भी मद्यनिषेध की अन्देखी की गई। शायद पहाड़ों में शराब राजस्व का एक महत्वपूर्ण साधन था।

**आजादी के पश्चात शराब विरोधी आन्दोलन**

स्वाधीनता के उपरान्त भी शासन द्वारा आंग्ल शासन की आबकारी नीति को अक्षरतः पालन किया जाता रहा। आजादी के पश्चात उत्तरप्रदेश में आंशिक मद्यनिषेध प्रयासों के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों को सम्मिलित न किये जाने पर यहाँ शराब का प्रचलन कमशः बढ़ता चला गया। 1960 के दशक में गढ़वाल के पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, लैन्सडौन, टिहरी गढ़वाल में टिचरी नाम से शराब का प्रचलन तेजी से हुआ।<sup>35</sup> फलस्वरूप विविध क्षेत्रों में आन्दोलन प्रारम्भ होने लगे। पौड़ी में शराब के विरुद्ध सशक्त आवाज दीपा देवी(इच्चागिरी माई) ने उठाई। उन्होंने 1955-56 पौड़ी टिचरी की दुकानों में आग लगा दी, टिचरी के विरोध के कारण वह टिचरी माई के नाम से प्रसिद्ध हुई।<sup>36,37,38</sup> 1962 में देहरादून में दर्जी का कार्य करने वाले गढ़वाल के सर्वोदय कार्यकर्ता सोहनलाल ने अपने सहयोगियों की सहायता से पोस्टकार्ड अभियान द्वारा प्रदर्शन किये। सरकार पर इसका असर न पडने पर कोटद्वार तथा पौड़ी में शराब की दुकानों पर तीन माह तक धरना दिया जाता रहा।<sup>39</sup> 1960 के दशक टिहरी में मद्यनिषेध आन्दोलन की बागडोर पर्यावरणविद्ध सुन्दरलाल बहुगुणा ने संभाली। टिहरी में सुन्दरलाल बहुगुणा ने शराब के विरुद्ध अनिश्चितकालीन उपहास प्रारम्भ किया जिसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। अन्ततः बादशाहीथौल में शराब की दुकान बंद करने के उपरान्त 13वें दिन उपहास खत्म किया।<sup>40</sup>

1962 में टिहरी के सिलियारा में पुनः आन्दोलन की लहर उठी, सुन्दरलाल बहुगुणा एवं उनकी पत्नी विमला बहुगुणा ने कच्ची शराब के विरुद्ध आन्दोलन छेड़ा, आन्दोलन के उग्र होने पर 1 अप्रैल 1965 में सरकार ने घनसाली में शराब की दुकान न खोलने की घोषणा की। इसी दौरान चमोली के चाँदपुरी गाँव की महिलायें बच्चों समेत आठ-दस मील पैदल जाकर शराब की दुकानों में धरना देती थी, इस आन्दोलन का नेतृत्व श्रीदेव सुमन की माँ तारा देवी ने किया।<sup>41</sup> पर्वतीय क्षेत्रों में उग्र शराब विरोधी आन्दोलन को देखते हुये सरकार ने 1969 पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ आदि में मद्यनिषेध लागू किया गया।<sup>42</sup> 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने केन्द्र में नशाबन्दी नीति लागू की। अतः अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून में भी पूर्ण शराब बन्दी लागू कर दी गई।<sup>43,44</sup> केन्द्र में कांग्रेस के पुनः सत्तासीन होने पर 1980 में पुनः शराब बन्दी नीति को हटा दिया गया। सरकार के

इस कदम से पहाड़ों में आक्रोश उत्पन्न होने लगा, 1984 में अल्मोड़ा एवं चौखुटिया में शराब विरोधी आन्दोलन पुनः<sup>45</sup> प्रारम्भ हुआ, देखते ही देखते संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में मद्य के विरुद्ध आन्दोलन नें उग्र रूप धारण कर लिया। 1 जनवरी 1984 में उत्तराखण्ड जनसंघर्ष वाहिनी के नेतृत्व में "नशा नहीं रोजगार दो" आन्दोलन शुरू किया गया। जिसमें महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। जो 1990 तक छिटपुट रूप से चलता रहा।<sup>46</sup> पुरुष वर्ग में शराब की लत से चूँकि सर्वाधिक पीडा महिलाओं को झेलनी पडती है। अन्ततः महिलाएँ जिन्होंने उत्तरांचल निर्माण में पुरुष वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आन्दोलन में सम्मिलित हुईं ने नये राज्य की कल्पना नशा मुक्त राज्य के रूप में देखने लगी।<sup>47</sup>

पृथक राज्य बनने के बाद भी सरकार ने महिलाओं की बिगडती स्थिति और युवाओं बढते मद्यपान की लत के बाबजूद भी मद्यनिषेध आन्दोलनों की अनदेखी कर राजस्व प्राप्ति का साधन बना रखा है। यद्यपि यदा कदा सरकार पर्वतीय प्रदेशों में धार्मिक आस्ता को ध्यान में रखकर मद्यनिषेध लागू कर देती है। किन्तु इसका भी पालन ठीक से नहीं किया जाता है।

#### आन्दोलन के असफलता के कारण

20वीं सदी के प्रारंभ से शुरू मद्यनिषेध आन्दोलन वर्तमान में 100 वर्षों बाद भी अपने लक्ष्य में पूर्ण सफल नहीं हो सका। आन्दोलन की असफलता के लिये प्रारम्भिक दौर से ही कुछ मूलभूत कारक मौजूद रहे हैं। आन्दोलन को कभी भी संपूर्ण जनता यदा अधिकांश पुरुष वर्ग, उच्च सभ्रांत वर्ग की महिलायें, युवा वर्ग का कभी भी पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं हो सका, आन्दोल में केवल उन्ही महिलाओं ने भाग लिया जिन्हें सर्वाधिक पीडा झेलनी पडी। इसलिये प्रारम्भ से ही आन्दोलन नेतृत्व विहीन रहा। संगठनशक्ति एवं अनुभवहीनता के चलते कभी भी आन्दोलन के लिये स्पष्ट कार्यक्रम नहीं बनाये गये। इसलिये विरोध के लिये कभी भी एकता स्थापित नहीं हो सका इसलिये आन्दोलन हमेशा बिखरा रहा। आन्दोलन को कभी भी मीडिया का खुलकर समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। प्रचार के अभाव में लोग जागृत नहीं हो सके न ही सरकार पर शराब बंधी के लिये दबाव जा सका। जबकि चिपको आन्दोलन जो चमोली के सीमांत गाँव से शुरू हुआ को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने में मीडिया की केन्द्रीय भूमिका रही। मद्यविरोधी शक्तियाँ हमेशा शक्तिशाली और संगठित रहीजो हमेशा से ही आन्दोलनकारियों पर भारी पडती रही शराब समर्थको द्वारा ब्रिटिश काल से ही शराब सेवन का प्रचार किया जाता रहा। स्वाधीनता के पश्चात कई बौद्धिकों ने प्रचार किया कि शराब पर्वतीय प्रदेश के विकास के लिये आर्थिकी का मुख्य जरिया है, सरकारी राजस्व का प्रमुख साधन है। ऐसे वर्ग द्वारा समय समय पर "शराब खुलाओ पहाड बचाओ" के नारे लगाये जाते रहे हैं।<sup>48,49</sup> आन्दोलन के असफलता के लिये सर्वाधिक उत्तरायी कारण सरकार की अविवेक पूर्ण नीतियाँ जिम्मेदार रही है। राजस्व के लालच में आन्दोलन को कभी भी सरकार का समर्थन नहीं मिल सका।

#### निष्कर्ष

किसी भी आन्दोलन की सफलताओं एवं असफलताओं से आन्दोलन का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता क्योकि आन्दोलन के तात्कालीन सफलताओं से कई आधिक लाभ दीर्घकालीन होते हैं, यद्यपि पर्वतीय प्रदेश उत्तरांचल में मद्यनिषेध आन्दोलन को अपने उद्देश्य में पूर्ण सफलता नहीं भी मिली हो फिर भी आन्दोलन लोगों में जागरुकता लाने में कुछ हद तक सफल रहा। ग्रामीण अंचलों में कच्ची शराब के उत्पादन को खत्म करने में सफल रहा। कही-कही आन्दोलनकारी शराब की दुकाने एवं गाँवों में मद्यसेवन बंद करने में भी सफल रहे हैं। यह आन्दोलन का ही परिणाम है कि आज भी नशे की संस्कृति के विरुद्ध सामाजिक संगठनों, महिला मंगलदलों गैर सरकारी संगठनों द्वारा नशा विरोधी आन्दोलन निरन्तर चलाये जा रहे हैं।

#### अंत टिप्पणी

1. कौटलीय अर्थशास्त्रम्, (हि0अ0 वाचस्पति गैरोला), चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, (2003) पृ0 200,201,202,203,204,
2. मनुस्मृति, द्वितीय भाग, (हि0अ0 शिवराज आचार्य), चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, (2007), पृ0 638,657,801,802,803,817,818,
3. शुक्रनीति, (हि0अ0 जगदीश चन्द्र मिश्र), चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, (1998) पृ0568
4. चन्द्र, शतीश, मध्यकालीन भारत, राजनीति, समाज और संस्कृति, आठवीं से सत्रहवीं सदी तक, प्रकाशन ओरियंट ब्लैक्सवॉन, प्रा0लि0 हिमायत नगर हैदराबाद,(2007) पृ0 93,
5. वर्मा, हरिशचन्द्र(सम्पा), मध्यकालीन भारत भाग-2, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, 21वाँ संस्करण 2009, पृ0 139,
6. मित्तल, ए0के0, तथा आर0 अग्रवाल, विश्व का इतिहास 1789 से 1919 ई0 तक, सत्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2003, पृ0 298 से 305 तक,
7. कौटलीय अर्थशास्त्रम्, उपरोक्त पृष्ठ,
8. डबराल,शिवप्रसाद,उत्तराखण्ड का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास ,भाग - 7 बीरगाथा प्रेस दोगडा, पौडी गढवाल, पृ0360
9. बिष्ट, प्रतापसिंह, चमोली जनपद, में मादक-द्रव्यों (नशीले पदार्थों) के सेवन की बढती प्रवृत्ति-एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, अप्रकाशित शोध ग्रंथ (1991), हे0न0ब0ग0वि0वि0 पृ018
10. रावत,चन्द्रपाल (सम्पा), गढवाल और गढवाल, विसर पब्लिशिंग क0,विकास मार्ग, पौडी, पौडी गढवाल(1997), पृ068
11. एटकिंसन, ई0टी0,द हिमायलन गजेटियर, खण्ड-3, भाग-2, कॉस्मो पब्लिकेशन, दिल्ली(1973), पृ0524
12. वाल्टन, गढवाल गजेटियर, (हि0अ0 प्रकाश थपलियाल, (2006) हिमालयन सचेतन संस्थान, आदि बदरी, चमोली, पृ0102,

13. वाल्टन, गढवाल गजेटियर, (हि0अ0 प्रकाश थपलियाल, 2006) हिमालयन सचेतन संस्थान, आदि बदरी, चमोली, उपरोक्त पृष्ठ,
14. रावत, चन्द्रपाल(सम्पा), गढवाल और गढवाल, विसर पब्लिशिंग क0, विकास मार्ग, पौडी, पौडी गढवाल (1997), पृ068
15. धस्माना, योगेश, उत्तराखण्ड में जनजागरण और आन्दोलनों का इतिहास, विसर पब्लिशिंग क0 देहरादून (2006), पृ0172,
16. प्री0 म्यूटिनी रिकार्ड (कुमाऊँ), एम0एल0आर0 वॉल्यूम-10, भाग-11, पृ069
17. योगेश धस्माना, पृ0172
18. विजयलक्ष्मी डबराल, छात्रों में मद्यपान की समस्या का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन जनपद टिहरी गढवाल के विशेष संदर्भ में अप्रकाशित शोध ग्रंथ (2010), हे0न0ब0ग0वि0वि0, पृ034
19. नवीन चन्द्र ढौंडियाल, एवं अन्य, पृथक पर्वतीय राज्य, भाग-1, (1993), श्री अल्मोडा बुक डिपो, मालरोड, पृ0215
20. अल्मोडा अखबार (साप्ताहिक), 2 जनवरी 1893,
21. नवीन चन्द्र ढौंडियाल, एवं अन्य, पृथक पर्वतीय राज्य, भाग-1, (1993), श्री अल्मोडा बुक डिपो, मालरोड, पृ0215
22. पाठक, शेखर, नशा एक षडयंत्र है, भाग-1, यामा रोहिला लॉज, नैनीताल, 1985, पृ01,
23. अल्मोडा अखबार (साप्ताहिक), 2 जनवरी 1893, उद्धरित धस्माना, योगेश, उत्तराखण्ड में जनजागरण और आन्दोलनों का इतिहास, विसर पब्लिशिंग क0 देहरादून (2006), पृ0172,
24. बिष्ट, प्रताप सिंह, चमोली जनपद, में मादक-द्रव्यों (नशीले पदार्थों) के सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति-एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, अप्रकाशित शोध ग्रंथ (1991), हे0न0ब0ग0वि0वि0 पृ0 20,
25. सिंह राकेश, उत्तरांचल में पिछले दो दशकों में महिलाओं की राजनीति सक्रियता के कारण, प्रभाव एवं सीमाओं का एक अध्ययन, गढवाल मंडल के विशेष संदर्भ में, अप्रकाशित शोध ग्रंथ (2008), हे0न0ब0ग0वि0वि0, पृ0164,
26. रावत, चन्द्रपाल (सम्पा), गढवाल और गढवाल, विसर पब्लिशिंग क0, विकास मार्ग, पौडी, पौडी गढवाल (1997), पृ068
27. कर्मभूमि स्वाधीन अंक, 12 सितम्बर 1972, लेख डबल सिंह नेगी, गढवाल की बारदोली उदयपुर, एक सिंहावलोकन,
28. कर्मभूमि स्वाधीन अंक, 26 जनवरी 1956, लेख बलदेव सिंह आर्य
29. वर्मा, डा0 आर0पी0, विभूतियाँ देवभूमि की (1997), सरस्वती प्रेस, देहरादून, पृ0154,
30. पंत सुरेश, (सम्पा0) उत्तरीय, प्रकाशन, बुद्धि बल्लभ तिवारी, जनकपुरी, नई दिल्ली, (1989), पृ0 61,
31. कर्मभूमि विशेषांक(कोटद्वार), 26 जनवरी 1956, पृ069,
32. कर्मभूमि स्वाधीन अंक, 26 जनवरी 1956,
33. डबराल, शिवप्रसाद, उत्तराखण्ड का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, भाग-8 बीरगाथा प्रेस दोगडा, पौडी गढवाल, पृ0248,
34. बिष्ट, प्रताप सिंह, चमोली जनपद, में मादक-द्रव्यों(नशीले पदार्थों) के सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति-एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, अप्रकाशित शोध ग्रंथ (1991), हे0न0ब0ग0वि0वि0 पृ0 14,
35. रावत, चन्द्रपाल (सम्पा), गढवाल और गढवाल, विसर पब्लिशिंग क0, विकास मार्ग, पौडी, पौडी गढवाल(1997), पृ068
36. उपरोक्त, पृ074,
37. दिनेश जोशी (सम्पा0) मध्य हिमालय, दिसम्बर 1996, नई दिल्ली, पृ012, उद्धरित, सिंह राकेश, उत्तरांचल में पिछले दो दशकों में महिलाओं की राजनीति सक्रियता के कारण, प्रभाव एवं सीमाओं का एक अध्ययन, गढवाल मंडल के विशेष संदर्भ में, अप्रकाशित शोध ग्रंथ (2008), हे0न0ब0ग0वि0वि0, पृ0164,
38. वर्तमान उत्तराखण्ड, जून 1995, टिंचरी माई, प्रकाशन भुवनेश्वरी महिला आश्रम, अंजनीसेण, टिहरी गढवाल,
39. दिनेश जोशी (सम्पा0) मध्य हिमालय, दिसम्बर 1996, नई दिल्ली, पृ012 उद्धरित उपरोक्त,
40. रावत, चन्द्रपाल(सम्पा), गढवाल और गढवाल, विसर पब्लिशिंग क0, विकास मार्ग, पौडी, पौडी गढवाल(1997), पृ068
41. उपरोक्त,
42. सिंह राकेश, उत्तरांचल में पिछले दो दशकों में महिलाओं की राजनीति सक्रियता के कारण, प्रभाव एवं सीमाओं का एक अध्ययन, गढवाल मंडल के विशेष संदर्भ में, अप्रकाशित शोध ग्रंथ (2008), हे0न0ब0ग0वि0वि0, पृ0164,
43. उप्रेती, प्रभात, एकाधिकार में पहचान खोती क्षेत्रीयता में संघर्षरत उत्तराखण्ड, गोपेश प्रकाशन, पृ0 97,
44. दिनेश जोशी (सम्पा0) मध्य हिमालय, दिसम्बर 1996, नई दिल्ली, पृ012 उद्धरित, उपरोक्त,
45. धनिका रेखा, उत्तरांचल में शराब समस्या, आधी जमीन विशेषांक, अक्टूबर-दिसम्बर, अंक4, प्रकाशन प्रा0लि0, एस0पी0वर्मा रोड, पटना, 2001, पृ0131
46. सिंह राकेश, उत्तरांचल में पिछले दो दशकों में महिलाओं की राजनीति सक्रियता के कारण, प्रभाव एवं सीमाओं का एक अध्ययन, गढवाल मंडल के विशेष संदर्भ में, अप्रकाशित शोध ग्रंथ (2008), हे0न0ब0ग0वि0वि0, पृ0168,
47. उपरोक्त,
48. नवीन चन्द्र ढौंडियाल, एवं अन्य, पृथक पर्वतीय राज्य, भाग-1, (1993), श्री अल्मोडा बुक डिपो, मालरोड, पृ0208
49. चन्द्र, विपिन्न, भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यमिक कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली वि. वि. (2015), पृ0 165,260